

यूपी गन्ना मूल्य तय करने पर जल्द निर्णय ले :केन्द्र P-10

राज्य मुख्यालय। आगामी पेरार्ई सत्र में राज्य की निजी चीनी मिलों के मालिकों व संचालकों द्वारा अपनी मिलों का संचालन न करने के फैसले पर केन्द्र सरकार की फिक्र भी बढ़ गई है। हाल ही में केन्द्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मंत्रालय के सचिव सुधीर कुमार की ओर से प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को पत्र लिखा गया है।

इस पत्र में प्रमुख सचिव चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को इस साल जून में लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि चीनी मिलों को दिये गए आश्वासन और डा.रंगराजन समिति की सिफारिशों के अनुरूप गन्ने और चीनी के दामों के बीच लिकेज स्थापित करने के सम्बंध में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। ताकि आगामी पेरार्ई सत्र में समय से मिलों का संचालन शुरू हो सके और गन्ना किसानों को भी कठिनाई न हो। अगर सरकार ने समय से जरूरी फैसले नहीं लिये तो अगले सत्र में चीनी मिलों का चलना कठिन होगा।

27/8/14